Classmate Date : Page :

गवर्नर जनरल विलियम बैंटिक ने मैकाले स्मरणार्थ लेख को 7 मार्च 1835 ई० को स्वीकृत कर आदेश दिया कि भविष्य में कम्पनी की सरकार यूरोपीय साहित्य विज्ञान को अंग्रेजी माध्यम द्वारा उन्नत करे तथा सभी खर्च इसी उद्देश्य से किए जाएं। देश में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बन गई। 1837 ई० में फारसी को न्यायालय की भाषा से हटा दिया गया और वहां का कार्यवाही भी धीरे-धीरे अंग्रेजी भाषा में होने लगा। हालांकि ~~कि~~ अंग्रेजी शिक्षा के ~~क~~ प्रचार-प्रसार के लिए Downward Filtration theory अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का चुनाव किया गया। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादन का तात्पर्य था कि सर्वप्रथम उच्च वर्ग को शिक्षित किया जाए इससे छन-छन कर शिक्षा का प्रभाव जन सामान्य तक पहुंचता रहेगा यानि ~~class~~ from classes to masses.

1854 ई० का चार्ल्स वुड डिस्पैच (Charles Wood dispatch).

शिक्षा के प्रचार ~~क~~ दूसरा चरण लार्ड डलहौजी के समय में प्रारम्भ हुआ था। 1853 ई० के चार्टर एक्ट में भारत में शिक्षा के विकास की समीक्षा हेतु एक समिति के गठन का प्रस्ताव किया गया था, सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में गठित समिति ने 1854 ई० में भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु एक वृहत्त योजना प्रस्तुत की जिसमें अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियामक पद्धति का गठन किया गया था। इसे Woods Dispatch या चार्ल्स वुड घोषणा पत्र-1854 कहा जाता है। चार्ल्स वुड के डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्नाकार्टा कहा जाता है। इसकी प्रमुख सिफारिशें थीं :- (1) ~~सरकार~~ सभी के लिए शिक्षा अवसर उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार इसे गंभीरतापूर्वक ले। (2) सरकार पाश्चात्य शिक्षा, कला, दर्शन, विज्ञान, साहित्य का प्रसार करे। (3) उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, परन्तु देशी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाए (4) देशी भाषायी प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित की जाएं और जिला स्तर पर - ऐंग्लो-वर्नाकुलर हाईस्कूल और संबंधित कॉलेज स्थापित किए जाएं। (5) अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएं (6) महिला शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए।

(7) शिक्षा क्षेत्र में निजी प्रयासों को प्रोत्साहन देने हेतु अनुदान पद्धति अपनाई जाए।

(8) कंपनी के पांच प्रांत में एक-एक शिक्षा विभाग के निर्माण का प्रावधान था जो ~~लोक शिक्षा के अधीन~~ 'लोक शिक्षा निदेशक' के अधीन कार्य संपादित करें।

(9) लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बंबई, मद्रास में तीन विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं जिनका कार्य परीक्षाएं संचालित करना हो।

21-1-Aug-20

वुड के डिस्पैच के क्रियान्वित होते ही अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत समाप्त हो गया। वुड के डिस्पैच के अधिकांश भागों पर अमल हुआ। 1858 में कलकत्ता मद्रास एवं बंबई में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। 1854 से प्राथमिक शिक्षा की बजाए माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा पर अधिक बल दिया गया। 1856 ई० में रुड़की एवं कलकत्ता में दो तकनीकी महाविद्यालय खोले गए। प्रारम्भी लेख्य पर बाद के आयोगों द्वारा कार्य किए गए।

हण्टर कमीशन (1882)

लार्ड रिपन ने 1882 ई० में डब्ल्यू डब्ल्यू हण्टर की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग का गठन किया जिसका उद्देश्य वुड्स के डिस्पैच की समीक्षा करना था। आयोग ने 1883 ई० में अपनी रिपोर्ट पेश की। आयोग ने प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल दिया। इसकी सिफारिशें थीं -

1. प्राथमिक शिक्षा उपयोगी विषयों में तथा स्थानीय भाषा में दी जानी चाहिए
2. प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेवारी जिला प्रशासन और म्युनिसिपलटी बोर्ड को देने की अनुशंसा।
3. उच्च शिक्षा संस्थाओं से सरकारी नियंत्रण समाप्त किया जाए।
4. सरकार कॉलेजों के लिए वित्तीय सहायता, विशेष अनुदानों की व्यवस्था करें।
5. महिला शिक्षा को अधिकाधिक प्रोत्साहित किया जाए।
6. धर्म निरपेक्ष एवं नैतिक शिक्षा पर जोर।
7. शिक्षा के क्षेत्र में ~~निजी~~ निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित किया जाए।

रैले आयोग (Raleigh Commission) और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम - 1904

लार्ड कर्जन ने शिक्षा पर सरकारी नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से ~~जनवरी 1902~~ शिमला में उच्च अधिकारियों के साथ एक सम्मेलन किया एवं उसके बाद जनवरी 1902 में थॉमस रैले, जो कि वायसराय की कार्यकारिणी समिति का सदस्य था के नेतृत्व में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। इस आयोग में दो भारतीयों - सैय्यद हुसैन बिलग्रामी और गुरुदास बनर्जी - को भी सदस्य नियुक्त किया गया। रैले आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम - 1904 पारित किया गया।

भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम - 1904 की संस्तुतियाँ :-

1. यूनिवर्सिटी सीनेट में फेलो सदस्यों की संख्या 50 से कम या सौ से अधिक नहीं होगी।
2. यूनिवर्सिटी के फेलो को सरकार ही मनोनित करेगी। फेलो का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा।
3. यूनिवर्सिटी के सीनेट द्वारा पारित किसी भी प्रस्ताव को सरकार वीटो (Veto) कर सकती है।
4. कॉलेज को मान्यता प्रदान करने या न करने के लिए सरकार की संस्तुति अनिवार्य होगी।
5. लेक्चरारों और प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए भी सरकार से अनुमति लेना आवश्यक होगा।

7 Aug 20.

5

अंग्रेजी शिक्षा का विकास

6. अशासकीय कॉलेजों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करना
स्पष्ट है कि कर्जन सरकार चाहती थी कि कॉलेजों/विश्वविद्यालयों के माध्यम से राष्ट्रीय सोच को पनपने न दिया जाए। भारतीय विश्वविद्यालय संसार में सर्वाधिक सरकारी विश्वविद्यालय बन गए थे।

1913 ई० का शिक्षा का सरकारी प्रस्ताव

21 फरवरी 1913 ई० को नवीन शिक्षा नीति के संबंध में एक सरकारी प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय की स्थापना करने तथा अध्यापकों के प्रशिक्षण को प्रभावी बनाने पर बल दिया गया था।

सैडलर आयोग 1917 ई०

1917 ई० में डॉ० माइकल सैडलर के नेतृत्व में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन हेतु सरकार ने एक आयोग गठित किया। सैडलर आयोग के अन्य सदस्य थे - आशुतोष मुखर्जी एवं डॉ० जियाउद्दीन अहमद। इस आयोग की मुख्य संस्तुतियाँ थीं :- (1) इण्टरमीडिएट कक्षाएँ विश्वविद्यालय से पृथक हों। (2) इण्टरमीडिएट परीक्षाओं का संचालन माध्यमिक बोर्ड करे। (3) कलकत्ता विश्वविद्यालय पर बंगाल सरकार का नियंत्रण हो। (4) स्नातक स्तर पर त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम हो। (5) प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक कुलपति नियुक्त किया जाए। (6) महिला शिक्षा पर विशेष बल दिया जाए।

सैडलर आयोग के सुझावों पर उत्तर प्रदेश में एक 'बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन' स्थापित किया गया। सैडलर आयोग ने अधिक से अधिक विश्वविद्यालय खोलने के सुझाव दिए जिसके आलोक में 1916 से 1921 तक सात विश्वविद्यालय खोले गए यथा- पटना विश्वविद्यालय, मैसूर, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ, उस्मानिया विश्वविद्यालय।

हार्टोग समिति (1929)

1929 ई० में फिलीप हार्टोग की अध्यक्षता में शिक्षा के विकास हेतु एक आयोग गठित किया गया था। इस आयोग की तीन प्रमुख संस्तुतियाँ थीं :- (1) प्राथमिक शिक्षा पर बल (2) ग्रामीण संस्कृति के छात्रों को मिडिल स्कूल की शिक्षा के उपरांत औद्योगिक व्यावसायिक शिक्षा दी जाए (3) विश्वविद्यालय की शिक्षा उपयुक्त एवं चुने हुए छात्रों को ही दी जाए। तभी विश्वविद्यालय के स्तर और गुणवत्ता को बनाए रखना संभव होगा।

अंग्रेजी शिक्षा का विकास

7 August (6)

वर्धा योजना (1937)

महात्मा गाँधी द्वारा 'हरिजन' में शिक्षा पर लिखे लेखों तथा अक्टूबर 1937ई० में वर्धा में आयोजित 'अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन' में इनके द्वारा शिक्षा पर प्रस्तुत योजना को मिलाकर बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना (Wardha Plan of Basic Education) प्रस्तुत की गई थी। इसकी प्रमुख संस्तुतियाँ थीं- (1) 7 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए (2) शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए (3) छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त हो जो Craft एवं Productivity से जुड़ा हो। शिक्षा को उद्योग धंधों से जोड़ा जाना चाहिए।

द्वितीय विश्वयुद्ध शुरू हो जाने से यह योजना स्थगित कर दी गई।

1944ई० की सार्जेन्ट योजना

1944ई० में भारत सरकार के शिक्षा परामर्शदाता सर जॉन सार्जेन्ट ने शिक्षा पर एक योजना प्रस्तुत की थी जिसकी संस्तुतियाँ थीं :-

(1) देश में प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए जाएं।
(2) 6 से 11 वर्ष के बालक-बालिकाओं के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए।
(3) 11-17 वर्ष की आयु के लिए 6 वर्ष की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए।
(4) उच्च विद्यालय दो तरह के होंगे - (1) शैक्षिक स्कूल (2) तकनीकी या व्यावसायिक स्कूल
(5) इंटरमीडिएट कोर्स को समाप्त कर दिया गया।
(6) 40 वर्षों के अन्दर सार्वभौमिक साक्षरता की उपलब्धि के लिए शिक्षा व्यवस्था का पुनर्निर्माण करना था।

राधाकृष्णन आयोग (1948-1949)

स्वतंत्रता के बाद 1948 में शिक्षा आयोग का गठन हुआ जिसका चेयरमैन डा० राधाकृष्णन को बनाया गया। ये जाने-माने शिक्षाविद् थे जो बाद में भारत के राष्ट्रपति चुने गए। अगस्त 1949 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की। मुख्य सिफारिशें :- (1) शिक्षा का भारतीयकरण (2) विश्वविद्यालय की शिक्षा से पहले 12 वर्षीय पाठ्यक्रम। (3) कृषि, कामर्स, इंजीनियरिंग, तकनीकी विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान आदि विषयों पर विशेष ध्यान। (4) विश्वविद्यालय की शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया जाएगा और परीक्षाओं का एकीकृत स्वरूप होगा। (5) शिक्षकों के वेतन में वृद्धि होगी। (6) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापित किया जाएगा और इसके विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता दी जाएगी।

MD. SANAM
ASST PROF HISTORY